□□□□ □□□□□□

KHANIJ SAMACHAR

Vol. 6, No-19

(As appeared in National/Local Newspapers Received in Central Library, IBM, Nagpur)

The Central Library, IBM, Nagpur is providing the Classified Mineral News Service since many years on monthly basis in print form. To expand this service to the IBM Offices all over India i.e. H.Q., Zonal & Regional Offices and to take a call of time, the Controller General, IBM desired to make this service online on fortnightly basis. The library officials made sincere efforts to make it successful. This is the 19th issue of Volume-6 for the service named Khanij Samachar for the period from 1st - 15th October, 2022 .The previous issue of Khanij Samachar Vol. 6, No.18 , 16th - 30th September, 2022 is already uploaded on IBM Website www.ibm.gov.in .

In continuation of this it is requested that the mineral related news appeared in the Local News Papers of different areas can be sent to Central Library via email ibmcentrallibrary@gmail.com (scanned copy) so that it can be incorporated in the future issues to give the maximum coverage of mining and mineral related information on Pan India basis.

All are requested to give wide publicity to it and it will be highly appreciated if the valuable feedback is reciprocated to above email.

Mrs. R. S. Wakode
Assistant Library & Information Officer
Central Library
ibmcentrallibrary@gmail.com
0712-2562847
Ext. 1210 , 1206

खनिज समाचार

KHANIJ SAMACHAR

A FORTNIGHTLY NEWS CLIPPING SERVICE

FROM

CENTRAL LIBRARY

INDIAN BUREAU OF MINES

VOL. 6, NO – 19 , 1st – 15th OCTOBER 2022

LOKMAT DATE : 1/10/2022 P.NO.5

खाणींपासून विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेला लाभ नाही

वेदचे उत्खननावर आधारित संमेलन १४ ऑक्टोबरपासून

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विदर्भात खनिज संपत्तीची कमतरता नाही. मात्र, त्याचा येथील अर्थव्यवस्थेला कवडीचाही लाभ नाही. दुसरीकडे मात्र खनिज संपत्तीच्या बळावर ओडिशा ५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवीत आहे. तेथे मोठी गुंतवणूक सुरू असून, प्रगतीही होत असल्याची खंत वेदने व्यक्त केली.

विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल (वेद) च्या वतीने १४ ऑक्टोबरपासून 'खनन' या विषयावर चिटणीस सेंटरमध्ये तीनदिवसीय संमेलनासह प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासंदर्भात माहिती देताना वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख म्हणाले, विदर्भातून कच्चा माल जातो. प्रत्यक्षात येथे यावर आधारित उद्योग उभे व्हायला हवे होते. यातून गुंतवणूक वाढून विदर्भाची अर्थव्यवस्था सक्षम झाली असती. या पत्रकार परिषदेला शिवकुमार राव, प्रदीप माहेश्वरी, व्ही. के. शुक्ला, रवी बोरटकर, राहुल उपगनलावार, अरुण देवरस, पंकज महाजन आदी उपस्थित होते.

या संमेलनात खनन क्षेत्रालाही एक मंच उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यावरून समस्या मांडल्या जाऊ शकतील. संमेलनाचे उद्घाटन कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री दादा भुसे आदींच्या उपस्थितीत होणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सावंत, महसूलमंत्री राधाकृष्ण वि पाटील, केंद्रीय कोळसा राज्यमं रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आदींनाही निमंत्रित करण्या आले आहे.

..धोरण आखले जावे

वेदच्या मते, छत्तीसगड, झारखंड आदी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सर्वसमावेशक खनन धोरण आखले जावे. यासंदर्भात सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

BUSINESS LINE DATE : 2/10/2022 P.NO.6

Bears pulling the strings

BULLION CUES. Last week's rally is nothing more than a corrective one

Akhil Nallamuthu
bl. research bureau

The precious metals appreciated last week as the dollar softened. Gold and silver in the international spot market were up 1 per cent and 0.7 per cent to end the week at $1,659.7 and $19 per ounce respectively. In the domestic market too, they posted gains. On the Multi Commodity Exchange (MCX), the December gold futures appreciated 1.3 per cent to close the week at ₹50,194 (per 10 gram). Similarly, the December silver futures went up 1.1 per cent as it closed at ₹56,858 (per kg).

WEAK FUNDAMENTALS

The latest data by the World Gold Council (WGC) shows that the weekly flows in global gold ETFs (Exchange Traded Funds) have been negative since the last week of June. For the week ended September 23, the net outflows from the global ETFs stood at nearly 28 tonnes.

The speculators too seem to be having a weak outlook on the yellow metal. The net longs on the COMEX, which stood at 462 tonnes on August 8, dropped to 143 tonnes on September 27. The charts too are indicating a weak outlook.

MCX-GOLD (₹50,194)

The December futures of gold on the MCX gained 1.3 per cent last week. However, the trend has been down since mid-August. The rollover looks very strong at nearly 99 per cent indicating that the participants have rolled over their short positions from October to December expiry indicating the broader expectation is bearish.

LACKLUSTRE GOLD

Latest World Gold Council data shows that the net flows in global gold ETFs have been negative since the last week of June. Also, net longs on COMEX have been steadily falling.

On the charts, even though the contract managed to close above ₹50,000-mark, it stays just below the trendline resistance at ₹50,200.

Moreover, the RSI and the MACD on the weekly chart shows that a decline from here is very much likely.

We expect gold futures to resume the descent from the current level or after moving up to ₹51,000 - a strong barrier.

The nearest supports are at ₹47,500 and ₹46,500. We forecast the contract to touch ₹46,500 before the end of this year.

MCX-SILVER (₹56,858)

Silver futures, which went up last week, remains below the key resistance band of ₹58,000-60,000. As long as it remains so, the trend will be considered bearish. The 20-week moving average coincides with this price band, making it a significant hurdle. Therefore, even though there was some short covering last week, the overall trend remains weak and the probability of a fall from here is high.

The price action on the weekly chart suggests the downtrend will resume with the nearest notable support at ₹52,000. If the downtrend extends below this level, subsequent support can be seen in ₹47,500-48,500 region. This is a strong support against which the contract can rebound.

DAINIK BHASKAR DATE : 3/10/2022 P.NO.18

कांद्री मॉयल में रेत सप्लाई में हेराफेरी

एक आरोपी गिरफ्तार

मुख्य सूत्रधार बबलू बर्वे समेत अन्य फरार

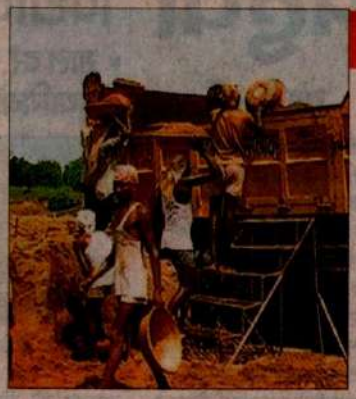

भास्कर संवाददाता | नागपुर.

कांद्री मैगनीज मॉयल मनसर में रेत सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपए की रेत चोरी कर राज्य सरकार को चूना लगाया गया है। पुलिस ने इस संबंध में अनुराग चौहान नामक एक आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया है। शनिवार को उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई और एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वही मुख्य सूत्रधार बबलू बर्वे तथा अन्य कुछ रेत माफिया फरार बताए जा रहे हैं।

यह है मामला : कांद्री मैगनीज मॉयल में मैगनीज निकालने के बाद मैगनीज निकाली हुई जगह में रेत भरी जाती है जिसे स्टोनिंग (stoing) कहा जाता है। इसे लेकर वर्ष 2018 से 19 के लिए निविदा निकाली गई थी। जिसे अनुराग चौहान, बालाघाट, मध्यप्रदेश निवासी ने नीलामी में लिया था। चौहान ने रेत सप्लाई का काम बबलू बर्वे तथा कामठी के एक चर्चित अपराधी से साठगांठ उन्हें दिया था। बर्वे कांद्री ग्रापं का उप-सरपंच व जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे का पति है। वर्ष 2018 से 19 में आसपास के कोई भी घाट की नीलामी नहीं हुई थी। ऐसे में रेत माफियाओं ने समीप के वाघोड़ा तथा सिहोरा घाटों से बड़े पैमाने पर रेत चोरी कर मध्यप्रदेश की बोगस रॉयल्टी पर मॉयल को रेत सप्लाई की थी,0 जबकि उस समय मध्यप्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत को रेत बेचने के अधिकार दिए थे। वो भी सिर्फ सरकारी काम के उपयोग के लिए ही था। मसलन उत्खनन कर मध्यप्रदेश के सरकारी कामों के लिए जीरो रॉयल्टी इश्यू की थी। जिसका दायरा भी 20 किमी का ही था। नदी से रेत उत्खनन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई थी। रेत माफियाओं के रैकेट द्वारा सभी ऑनलाइन रॉयल्टी को बुक कर रॉयल्टी का इस्तेमाल कांद्री मैगनीज मॉइल में धड़ल्ले से किया गया। इसके अलावा सावनेर से पारशिवनी रोड का काम करने वाली कंपनी एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में भी मध्यप्रदेश की इसी रॉयल्टी का इस्तेमाल बे-रोकटोक किया गया।

रेत रॉयल्टी के क्लीयरेंस से खुली पोल : मॉयल के अधिकारियों को शक होने पर रेत माफियाओं ने सिवनी, मंडला तथा बालाघाट से रॉयल्टी का जुगाड़ कर क्लीयरेंस लाया गया, जो वैध था, लेकिन रॉयल्टी में टाइमिंग की गड़बड़ी से मामला गड़बड़ा गया। टाइमिंग में काफी खामियां पाई गईं। जिसको लेकर मॉइल अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक नागपुर तथा रामटेक पुलिस को शिकायत की थी। बबलू बर्वे की पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष होने से पुलिस भी कार्रवाई करने से कतराती रही। आरोपियों को जिले के राजनेताओं का वरदहस्त प्राप्त होने से मामला काफी दिनों तक अटका पड़ा था। वहीं राज्य में सत्ता पलटने के बाद आरोपियों की कारगुजारी सामने आने लगी हैं।

मंत्री दादा भुसे के रामटेक दौरे से मामले में आया नया मोड़ : सितंबर महीने में विधायक आशीष जायस्वाल ने मंत्री दादा भुसे को रामटेक बुलाया था। अंतिम क्षण में मंत्री को मॉयल के कार्यालय ले जाया गया था। मंत्री खुद वकील होने से मामले को मॉयल के हेडक्वार्टर, सदर नागपुर भेजा गया, क्योंकि टेंडर की सारी प्रक्रिया हेडक्वार्टर से ही थी। मामला भी सदर थाने में मॉयल खदान के अधिकारी ने लिखित तौर पर दर्ज कराया।

लॉकडाउन के दौर में भी सक्रिय रहे : उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2018 से 2019 में कोरोना संक्रमणकाल के चलते देश में लॉकडाउन था। जिले के घाट की नीलामी भी नहीं हुई थी। ऐसे में करोड़ों रुपए की रेत अवैध तरीके से बेचने के बाद भी राजस्व विभाग तथा पुलिस महकमे की अनदेखी भी समझ से परे है। फिलहाल पुलिस ने अनुराग चौहान को गिरफ्तार किया है। बाकी फरार आरोपियों में सूत्रधार बबलू बर्वे, सदे आलम, जमशेद अहमद सिद्दीकी, मो. नईम सिद्दीकी, रेड्डी ट्रेडर्स मनसर का समावेश है।

BUSINESS LINE DATE : 4/10/2022 P.NO.9

Jewellers using import duty loophole to bring in gold in guise of 'platinum alloy' at lower rate

Reuters
Mumbai/New Delhi

India's platinum imports in September jumped to a record high as refiners imported a large amount of gold containing small amounts of platinum but registered the purchases with Customs as platinum alloy to avoid paying higher duties, government and industry officials told *Reuters*.

Such masking was possible due to what a tax official said was a loophole created by a change in policy in July whereby differential import duties were levied on gold, silver and platinum, distinct from the previous policy of having the same tax rates for all the three precious metals.

In July, New Delhi raised the import duty on gold to 15 per cent but kept the tax on platinum imports unchanged at 10.75 per cent.

"The duty change allowed importers to exploit a loophole in the system. They initially, in August, imported a small quantity with 3 per cent platinum and got it cleared by Delhi Customs as platinum alloy," said a senior industry official, who declined to be named.

As their imports were cleared, more gold was brought in the garb of platinum by refiners and trade houses, showing a jump in platinum imports to around 27 tonnes in September from 1.14 tonnes a year ago, trade and government sources said.

'TAKING ADVANTAGE'

In calendar 2021, India had imported 10.59 tonnes of platinum, according to data compiled by the Ministry of

Commerce and Industry. A Mumbai-based bullion dealer said refiners were taking advantage of the rule that says, "An alloy containing 2 per cent or more, by weight, of platinum is to be treated as an alloy of platinum."

"The rule was framed when platinum prices were higher than gold. In recent years platinum prices have crashed.

"But still traders couldn't use the rule as the import duty on both the commodities was same. After July's duty hike, refiners started using this loophole," the dealer said.

Dubai-based gold refiners were mixing 2-5 per cent platinum in gold bars exclusively for Indian buyers, said a bullion dealer based in the emirate, declining to be named.

Import duty on platinum hiked to 15.4%

India has raised total import duty on platinum to 15.4 per cent from 10.75 per cent, the government said in a notification on Monday, seeking to bring parity in import duty structure between gold and platinum. In July, New Delhi raised import duty on gold to 15 per cent but then kept the tax on platinum imports unchanged at 10.75 per cent. REUTERS

BUSINESS LINE DATE : 4/10/2022 P.NO.8

Copper to pause, dip

COMMODITY CALL.

Akhil Nallamuthu
bl research bureau

Copper futures resumed their downtrend after facing the resistance band of ₹680-700 in the second week of August. Since then, it has been forming lower highs and lower lows, tracing a falling channel.

There was a short term build-up between September 9 and 23 as the cumulative Open Interest (OI) of copper futures increased from 5,760 contracts to 7,409 as the price fell from ₹655 to ₹630. Nevertheless, it saw an appreciation last week and parallelly, the cumulative OI came down to 5,456 contracts during the weekend.

However, it is not an indication of a bullish trend reversal as the contract is likely to meet the upper end of the falling channel at around ₹660 — a resistance. The 50-day moving average is at ₹650, another barrier that could block the recovery.

This indicate that the contract could begin declining between ₹643 and ₹660. Yet, there could be a pause before that.

We have been recommending shorts over the past month at various price points between ₹640 and ₹675 with a stop-loss at ₹715. Traders who hold these positions can continue to hold. But modify the stop-loss to ₹685 now.

Bring the stop-loss further down to ₹670 when the contract slips below the support of ₹600. Tighten it further to ₹615 when the contract touches ₹585. Exit the shorts at ₹550.

Fresh shorts can also be initiated at the current level with above-mentioned stop-loss and target levels.

THE ECONOMIC TIMES DATE : 5/10/2022 P.NO.7

Platinum Import Duty Increased to 15.4%

Our Bureau

New Delhi: India has raised import duty on platinum to 15.4%, bringing it closer to gold.

The move comes after cases of misuse of duty differential between Platinum and Gold came to light, said a government official. Platinum alloys with just 4% platinum and the rest gold were being cleared at the reduced duty of 11% and the increase will prevent the misuse of duty gap. Platinum and palladium for use in manufacturing precious metal chemicals, compounds and catalytic converters will continue at 7.5%.

The Centre had in July raised import duty on gold to 15%, including a 2.5% agriculture infrastructure development cess (AIDC), taking the total import duty to 15 %. However, it kept the tax on imported platinum unchanged at 10.75%.

THE TIMES OF INDIA DATE : 5/10/2022 P.NO.4

IBM holds Hindi Pakhwada concluding ceremony

Concluding and prize distribution ceremony of **Hindi Pakhwada 2022** was organized under the chairmanship of **Pankaj Kulshrestha,** chief controller of mines (in-charge) at **Indian Bureau of Mines** (HQ) recently. CMD of MOIL Limited, **Mukund Choudhary** was the chief guest. **YG Kale,** mine controller (TMP) and Rajbhasha officer, and other senior officers, personnel were present on the occasion. **Hindi book** of IBM Nagpur **'Khan Bharti 2022'** was also released on the occasion. Kulshrestha stressed on the maximum use of official language Hindi. Choudhary threw light on the importance of Rajbhasha. **Kulshrestha and Kale** distributed awards to the winners of various competitions of Hindi Pakhwada. **Vinay Kumar Saxena** conducted the proceedings while **Asim Kumar** proposed a vote of thanks.

BUSINESS LINE DATE : 7/10/2022 P.NO.8

Lead jumps as stocks fall

Reuters

Lead prices hit a seven-week high on Thursday as inventories slumped amid worries about smelter shutdowns while copper and zinc rose after the London Metal Exchange (LME) imposed restrictions on metal from a Russian company.

Trading was choppy as investors also tried to factor in potential loss of demand from aggressive increases to interest rates to curb inflation. Three-month LME lead gained as much as 2.8 per cent at $2,093.50 a tonne in volatile trading - its highest since August 18. "The supply side shocks are just reverberating," said Nitesh Shah, commodity strategist at WisdomTree.

ADDING FUEL TO FIRE

"The OPEC announcement is just adding fuel to the energy crisis that was already raging. Smelters may shut down more of their operations and mining operations are going to be more difficult." OPEC+ agreed steep oil production cuts on Wednesday.

Other metals gained after the LME restricted new copper and zinc deliveries from Russia's Ural Mining & Metallurgical Co Ural and a subsidiary after Britain imposed sanctions on its controlling shareholder, Iskander Makhmudov.

Zinc was the biggest LME gainer, advancing 0.9 per cent to $3,070 a tonne.

BUSINESS LINE DATE : 9/10/2022 P.NO.1

Gold diversion to China, Turkey 'not to affect India'

Suresh P Iyengar
Mumbai

The recent decision of gold-supplying global banks to divert the precious metal marked for India delivery to China and Turkey is not expected to affect jewellery supply or demand during this festival and wedding season.

Most jewellery manufacturers in India stocked up enough gold even a month back in anticipation of better demand and in view of the steady depreciation of the rupee which makes imports costlier.

'NO SHORTAGE'

Kumar Jain, national spokesperson, India Bullion and Jewellers Association, said the decision to divert gold from India will not have any impact as jewellers plan for the festival season sales at least a couple of months in advance and there is enough supply of bullion across the globe.

GLITTERING SALES. India, which ships in about 800-900 tonnes of gold annually, is the No 2 importer after China

India imports 800-900 tonnes of gold annually, and is the second largest buyer after China.

There is also domestic supply of 250-300 tonnes through recycling of old jewellery, he said.

With Indian households' gold holdings estimated at 25,000 tonnes, it is unlikely that there will be a shortage due to some tactical decision of a few global gold suppliers, said Jain, who runs a jewellery showroom in Zaveri Bazar, the heart of gold trade in Mumbai.

ECONOMIC TURBULENCE

Large-scale gold imports by Turkey and China are largely due to their economic turbulence, said a banker, who did not want to be named.

Turkey's gold imports surged over five times to $3 billion in September, as the country's annual inflation accelerated to a 24-year high of 83 per cent with 'transport' prices surging 118 per cent and 'food and non-alcoholic drinks' rising 93 per cent.

Despite the surging inflation, Turkey's central bank reduced interest rates from 14 per cent to 12 per cent and the country's President promised further cuts.

Similarly, China has restricted gold supply by allowing only accredited banks to import gold with quantities set by the People's Bank of China.

With a sharp slide in the value of the yuan against the dollar, spot gold prices in dollar terms dropped over 8 per cent in the September quarter and under 3 per cent in yuan.

In contrast, India is readying for a major wedding season with 155 *muhurat*, or auspicious, days in this Hindu calender year up from 85 last year. This trans-

BUSINESS LINE DATE : 7/10/2022 P.NO.8

MCX aluminium: Stay away from any bets now

Gurumurthy K
bl research bureau

The aluminium futures contract traded on theMCX has risen sharply by more than 9 per cent over the past week. The contract is trading at ₹210 per kg. This has negated our bearish outlook of a fall to ₹186.50 and ₹181.5 in this column last week.

The outlook is bullish. The contract has room to test ₹213 and even ₹215-217 on the upside in the next week or two. The region of ₹215-217 is a strong resistance.

A break above ₹217 might be difficult. Inability to rise past ₹217 can trigger a pullback towards ₹210 and even ₹205-200 thereafter. If the contract manages to breach ₹217, the bullish momentum can increase. In that case, the futures contract can extend the upside to ₹221. Support is at ₹203. Below that, the ₹201-₹200 zone will be the next important support. The contract will have to fall below ₹200 to come under pressure again.

Although the immediate outlook is bullish, the risk-reward ratio does not favour going long at current levels. So, we suggest staying out of the market for now. Watch the price action in the ₹215-217 and trade positions can be taken accordingly.

THE HITAVADA
DATE : 10/10/2022 P.NO.4

'India steel output up 2.5 per cent at 30 MT in Jul-Sept'

INDIA'S crude steel output rose by 2.56 per cent to 30.06 million tonne (MT) during the July-September period of the ongoing financial year.

As per research firm SteelMint, the top six steel makers -- SAIL, Tata Steel, JSW Steel, JSPL, AMNS India and RINL -- produced 18.29 MT steel, the rest 11.77 MT came in from the secondary sector.

The country had produced 29.31 MT of steel during the same quarter in the preceding 2021-22 financial year, according the data shared by SteelMint.

During the said quarter last fiscal, large producers had jointly manufactured 18.39 MT steel, while the secondary industry produced 10.92 MT, it said.

During the quarter ended September 30, 2022, steel exports fell to 1.41 MT from 4.20 MT in the year ago period, registering a year-on-year (y-o-y) fall of 66.43 per cent.

The domestic consumption was 11.33 per cent higher at 27.52 MT, as against 24.72 million tonne (MT) in July-September 2021.

On the outlook for the sector during the running October-December quarter, SteelMint said "the production is expected to increase in the quarter as mills have resumed production after a brief maintenance shut down taken in the last quarter."

According to SteelMint exports will continue to remain low in the third quarter owing to the export duty and subdued global market because of high energy cost and inflation.

On May 21, the Government hiked the duty on exports of iron ore by up to 50 per cent and for a few steel intermediaries to 15 per cent.

It also waived customs duty on the import of some raw materials, including coking coal and ferronickel, used by the steel industry, according to SteelMint.

THE TIMES OF INDIA DATE : 10/10/2022 P.NO.4

Chanda can be first Maha district to have copper mines: Report

Mazhar Ali | TNN

Chandrapur: Having earned the distinction as back gold district for high deposits of coal, Chandrapur is now looking towards copper revolution.

GROUND GAIN

Primary explorations have revealed vast deposits of copper ore in the district. Chandrapur would be the first in the state to have copper mines, if its mining project goes ahead.

Sources said the administration has been exploring the potential of copper mining in the district since quite some time. Large deposits of copper ore have been found at Thanewasana (Pombhurna taluka), Dubarpeth (Gondpipri taluka), Lavari and Adegaon-Motegaon (Chimur taluka) in the district.

Primary exploration of the copper deposits at Thanewasana and Dubarpeth with the help of directorate geology and mining (DG&M) and Geological Survey of India (GSI) has been completed, while the exploration of Lavari and Adegaon-Motegaon blocks is underway.

The administration has prepared and forwarded its preliminary report detailing the potential of copper mining at Thanewasana and Dubarpeth to the government. Based on the report, multinational mining major Vedanta Limited has acquired both these blocks.

Sources informed that the government of Maharashtra had earlier invited bids for grant of two copper composite licenses (prospecting licence cum mining lease) in February, 2019.

According to Tamra, a web portal of the Union ministry of mines, Dubarpeth and Thanewasana copper blocks having estimated size of 816.29 hectares and 768.62 hectares have been allocated to Vedanta Limited through e-auction later in the same year.

NAVBHARAT DATE : 10/10/2022 P.NO.7

खुलेंगी तांबे की खदानें, प्रशासन जुटा तैयारियों में, जिले को होगा फायदा

उद्योग रहित गोंडपिपरी, पोंभूर्णा व चिमूर तहसील में मिला भंडार

■ चंद्रपुर, ब्यूरो. कोयला, चूना पत्थर (सीमेंट) और वन संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध जिला अब तांबे की क्रांति से जुड़ रहा है. प्रारंभिक खोज में पता चला है कि जिले के गोंडपिपरी, पोंभूर्णा और चिमूर तहसीलों में तांबे के प्रचुर भंडार हैं. यदि खनन परियोजना आगे बढ़ती है, तो चंद्रपुर राज्य का पहला जिला होगा, जहां तांबे की खदानें होंगी. खनन विभाग के सूत्रों ने बताया कि अनुसंधान कार्य जोरों पर है और राज्य सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से जिले में तांबे के खनन की संभावनाएं तलाश रही हैं. यह जानकारी खनिकर्म विभाग ने दी है. सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2019 में 2 कॉपर कंपोजिट लाइसेंस (प्रास्पेक्टिंग लाइसेंस सह खनन पट्टा) देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं. कॉपर (तांबा) केंद्रीय खान मंत्रालय के वेब पोर्टल के अनुसार, दुबारपेठ और ठाणेवासना में कॉपर ब्लाक है. लगभग 816.29 हेक्टेयर और 768.62 हेक्टेयर भूमि वेदांता लि. को उसी वर्ष ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित की गई थी. जहां दुबारपेठ खदान में 1.343 मिलियन टन का भंडार है, वहीं ठाणेवासना ब्लाक में 8.02 मिलियन टन तांबे का भंडार होने का अनुमान है.

वेदांत ने अधिग्रहित किया ब्लाक : जिले के ठाणेवासना (पोंभूर्णा तहसील), दुबारपेठ (गोंडपिपरी तहसील), लावारी और अडेगांव-मोटेगांव (चिमूर तहसील) में तांबा अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं. जियोलाजी एंड माइनिंग (डीजीएंडएम) और जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (जीएसआई) की मदद से ठाणेवासना और दुबारपेठ में तांबे के भंडार की प्रारंभिक खोज पूरी कर ली गई है. लावारी और अडेगांव-मोटेगांव ब्लाक की खोज प्रगति पर है. प्रशासन ने ठाणेवासना और दुबारपेठ में तांबे के खनन की संभावनाओं का विवरण देते हुए एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी है. स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर, बहुराष्ट्रीय खनन प्रमुख वेदांत लिमिटेड ने प्रास्पेक्टिंग और खनन के लिए इन दोनों ब्लाकों का अधिग्रहण किया है. दोनों ब्लाक कंपनी को 50 वर्ष के लिए आवंटित कए गए हैं.

THE ECONOMIC TIMES DATE : 10/10/2022 P.NO.9

Global Slowdown Forces Textile, Diamond Units to Extend Leaves

Move to help avoid job cuts; major markets in Europe, US grappling with slowdown

Sutanuka.Ghosal
@timesgroup.com

Kolkata: Surat's diamond cutting units have extended the Diwali holidays for their workers to 25 days this year. At Tirupur, most of the garment manufacturing units have cut the working days to four a week from six and given two weeks of Diwali holidays instead of the usual one.

But there isn't anything to cheer about.

The businesses are down as their major markets, the US and Europe, are grappling with a slowdown. Orders for readymade garments, for shipments in December and January to meet summer season demand, are 40% lower compared with this time last year, according to industry insiders. Diamond shipments too have taken a hit as consumers in the US are cutting down on discretionary purchases amid recession worries. For the exporters, giving more off days to workers is a short-term measure to avoid job cuts.

"Diwali holidays have been extended so that the workers do not lose jobs," said Bhavesh Tank, vice-president of the Diamond Workers' Union, Gujarat, adding: "We are not paid during holidays. We get paid against the days we work."

At the diamond cutting units in Surat, Diwali holidays will begin on October 21 and continue till November 15. The workers usually get 15 days.

"The US market is very slow, and the offtake has come down," said Vijaykumar Mangukiya, a diamond exporter and chairman of the Gujarat region of the Gem & Jewellery Export Promotion Council. Demand is weak also in China, the second biggest market for India's diamond exporters, while the Russia-Ukraine war has hurt exports to the European region, he said. "That is why the units have extended the Diwali holiday this year." The 4,000 diamond units in Surat employ around 8,00,000 people.

Tamil Nadu's Tirupur cluster has 25,000 units, including suppliers of accessories for readymade garments, employing about 6,00,000 people.

THE ECONOMIC TIMES DATE : 10/10/2022 P.NO.1

CABINET NOTE MAY BE MOVED AFTER DISCUSSIONS

Duty Refunds likely for Steel, Pharma & Chemical Exports

Commerce and finance ministries in talks to include 3 sectors hit by falling demand under RoDTEP

Kirtika.Suneja@timesgroup.com

New Delhi: India could be looking at extending a key export scheme to pharmaceuticals, chemicals and steel products, eyeing measures to support exports hit hard by falling demand in advanced economies. Discussions have started between the ministries of commerce & industry and finance on including these sectors under the Refund of Duties and Taxes on Exported Products or RoDTEP scheme.

The input duty remission scheme for exporters was implemented from January 1, 2021 but had excluded these sectors. "A proposal to include these sectors under RoDTEP is under discussions," a government official, privy to the deliberations, told ET.

A cabinet note could be moved after discussions with the finance ministry, according to the official.

The scheme offers 0.3-4.3% incentive to 8,555 products in many employment-generating sectors such as marine, agriculture, leather and gems & jewellery.

The government has provided around Rs 13,000 crore under RoDTEP for the refund of duties and taxes such as value added tax on fuel used in transportation, mandi tax and duty on electricity used during manufacturing, which were so far not being refunded. As per the official, the commerce department will need an additional Rs 2,000 crore to expand the coverage under the scheme.

Extending Support

Refund of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme implemented from Jan 1, 2021

Offers 0.3-4.3% incentive to **8,555** products in sectors such as marine, agri, and gems & jewellery

But excludes pharma, steel and chemicals

Commerce ministry will need additional **₹2,000 cr** to expand coverage under scheme

Chemical sector eyes a remission rate of **2.3-2.9%**

Pharma industry seeks 5-6%

It's a crucial move as India's Sept exports shrank 3.5% on weak global demand

Diamond, Textile Units Extend Workers' Leaves

Surat's diamond cutting units have extended the Diwali holidays for their workers to 25 days this year to avoid job cuts. At Tirupur, most of the garment factories have cut the working days to four a week and given two weeks of Diwali holidays. **Sutanuka Ghosal** reports. ▸▸ 9

THE ECONOMIC TIMES DATE : 10/10/2022 P.NO.5

Gold Is Heading East amid Falling Prices

Asian buyers snap up the metal as western investors dump it with interest rates on the rise

Bloomberg

There's a global migration underway in the gold market, as western investors dump bullion while Asian buyers take advantage of a tumbling price to snap up cheap jewellery and bars.

Rising rates that make gold less attractive as an investment mean that large volumes of metal are being drawn out of vaults in financial centres like New York and heading east to meet demand in Shanghai's gold market or Istanbul's Grand Bazaar.

In fact, it can't move fast enough. Logistical issues combined with quirks of the market are making it difficult for traders to get enough bullion where it's wanted. As a result, gold and silver are selling at unusually large premiums over the global benchmark price in some Asian markets.

"The incentive to hold gold is a lot lower. It's going from west to east now," said Joseph Stefans, head of trading at MKS PAMP SA, a gold refining and trading firm. "We are trying to keep up as best we can."

The rotation of metal around the world is part of a gold-market cycle that has repeated for decades: when investors retreat and prices drop, Asian buying picks up and precious metals flow east, helping to put a floor on the gold price during times of weakness.

Then, when gold eventually rallies again, much of it returns to sit in bank vaults beneath the streets of New York, London and Zurich. Since peaking in March, gold prices have tumbled 18% as the Federal Reserve's aggressive rate hikes caused mass liquidation by financial investors.

More than 527 tonnes of gold has poured out of New York and London vaults that back the two biggest Western markets since the end of April, according to data from the CME Group and London Bullion Market Association.

At the same time, shipments are rising into big Asian gold consumers like China, whose imports hit a four-year high in August.

While plenty of gold is heading east, it's still not enough to meet

demand. Gold in Dubai and Istanbul or on the Shanghai Gold Exchange has traded at multi-year premiums to the London benchmark in recent weeks, according to MKS PAMP, a sign that buying is outstripping imports.

"Demand typically picks up when prices fall," said Philip Klapwijk, managing director of Hong Kong-based consultant Precious Metals Insights. "Buyers want to source metal at the lower price and in the local physical market in question there may not be sufficient metal available when the price falls, so the local premium increases."

Gold in Thailand is also trading at a premium to London prices, due to a lack of supply and weakness in the local currency, according to Jitti Tangsithpakdi, the president of Thailand's Gold Traders Association. In India, it is silver that is seeing big premiums. The differential has soared recently to $1, more than triple the usual level, according to consultancy Metals Focus.

"Right now the demand for silver is huge as traders restock," said Chirag Sheth, the firm's principal consultant in Mumbai. "Premiums could remain elevated during the festival season that concludes with Diwali."

Analysts say that much of the precious metals feeding Asia's appetite is coming out of vaults run by CME Group, which back the Comex futures market in New York. Market dislocations early in the pandemic drove a massive surge in prices there, forcing banks to build large stockpiles to cover their futures positions. In recent months gold has traded at a discount on the Comex compared to London, and those inventories are now being drawn down to meet Asian demand.

NAVBHARAT DATE : 10/10/2022 P.NO.9

इस्पात उत्पादन 2.56% बढ़ा

दिल्ली. भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन जुलाई-सितंबर की तिमाही में 2.56 प्रश बढ़कर 3 करोड़ टन से कुछ अधिक रहा है. अनुसंधान कंपनी स्टीलमिंट के अनुसार देश की शीर्ष 6 इस्पात कंपनियों सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, एएमएनएस इंडिया और आरआईएनएल ने कुल 1.82 करोड़ टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया. शेष 1.17 करोड़ टन का उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र ने किया. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में देश का कच्चे इस्पात का उत्पादन 2.93 करोड़ टन रहा था. स्टीलमिंट द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, तिमाही के दौरान बड़े इस्पात विनिर्माताओं का उत्पादन 1.83 करोड़ टन से अधिक रहा, जबकि द्वितीयक श्रेणी के उत्पादकों ने 1.09 करोड़ टन का उत्पादन किया.

THE HITAVADA (CITYLINE) DATE : 11/10/2022 P.NO.6

'Gems, jewellery exports grow by 27.17 pc in Sept'

■ Business Bureau

INDIA'S gems and jewellery exports rose 27.17 per cent to Rs 30,195.21 crore (USD 3,765.51 million) in September compared to the same month last year, the Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) said on Monday.

The overall gems and jewellery exports stood at Rs 23,743.46 crore (USD 3,227.63 million) in September 2021, according to GJEPC data.

For the cumulative period of April-September 2022, the overall gross exports witnessed a growth of 12.82 per cent to Rs 1,61,545.06 crore (USD 20,580.11 million) compared to Rs 1,43,187.15 crore (USD 19,359.01 million) for the same period last year.

"The global consumer sentiments across key markets of the USA, Middle East and Hong Kong have continued to be favourable for the sector. Thailand, Switzerland, Singapore have emerged as new growth markets. The sector has achieved 45 per cent of its annual export target of USD 45.7 billion for the year 2022-23, and I am confident that if the current momentum continues, the sector will achieve its set target during the second half of FY23," GJEPC Chairman Vipul Shah said.

Meanwhile, the overall gross export of Cut and Polished Diamonds (CPD) grew 21.99 per cent in September to Rs 17,107.64 crore (USD 2,134.91 million) against Rs 14,023.78 crore (USD 1,906.72 million) in the corresponding period of 2021. In September, the total export of gold jewellery (both plain and studded) witnessed a growth of 25.42 per cent to Rs 7,067.17 crore (USD 880.25 million) against Rs 5,634.86 crore (USD 765.7 million) for the same period last year.

The total gross export of plain gold jewellery witnessed a growth of 30.78 per cent to Rs 2,556.40 crore (USD 318.36 million) compared to Rs 1,954.78 crore (USD 265.74 million) for the same month last year.

For September, the total gross export of all kinds of studded gold jewellery went up by 22.57 per cent to Rs 4,510.77 crore (USD 561.89 million) compared to Rs 3,680.08 crore (USD 499.96 million) in September last year.

During April-September, the provisional gross export of polished lab-grown diamonds soared 70.26 per cent to Rs 7,407.56 crore (USD 943.63 million) against Rs 4,350.81 crore (USD 587.76 million) for the same period last year.

The provisional gross export of coloured gemstones during April-September jumped by 54.62 per cent to Rs 1,642.93 crore (USD 209.27 million) against Rs 1,062.57 crore (USD 143.7 million) for the same month of FY22.

BUSINESS LINE DATE : 11/10/2022 P.NO.9

Coal Ministry issues allocation orders for 12 mines

Our Bureau
New Delhi

HUMAN IMPACT. The mines will provide jobs to 28,800 people

The Coal Ministry on Monday said it has issued allocation orders for 12 coal mines for which the Coal Mine Development and Production Agreement was signed on August 17. Of these, seven are under the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, while the remaining mines are under Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957. The cumulative Peak Rate Capacity (PRC) of the mines for which allocation or vesting orders have been issued is 21 million tonnes per annum (MTPA) and geological reserve is 2.3 million tonnes (mt).

These mines are expected to generate an annual revenue of ₹3,569 crore, calculated on the basis of PRC and will attract a capital investment of ₹3,208 crore. It will provide employment to around 28,800 people.

The vesting/allocation orders have now been issued for 39 mines under commercial auctions with cumulative PRC of 83.10 MTPA. This will generate annual revenue of ₹11,380 crore and employment for 1,12,344 people.

THE ECONOMIC TIMES DATE : 12/10/2022 P.NO.6

JSW Cement Lines Up ₹3,200 crore to Increase Capacity Post Springway Buy

Our Bureau

Mumbai: JSW Cement on Tuesday announced a ₹3,200-crore investment to build a 5 million tonnes per annum (mtpa) cement manufacturing plant, following the acquisition of Springway Mining assets of India Cements in Madhya Pradesh.

The acquisition gives JSW Cement access to limestone reserves of 106 million tonnes, including a mining lease valid until 2065, the company said. On Monday, India Cements had informed the bourses that it was selling it's Springway Mining assets to JSW Cement for ₹477 crore to pare its debt.

JSW Cement has set a target of achieving 50 mtpa cement manufacturing capacity from 17 mtpa at present. It had raised a ₹400-crore sustainability-linked loan from MUFG Bank India last week to fund its expansion plans.

JSW Cement has set a target of achieving 50 mtpa cement manufacturing capacity from 17 mtpaat present

Seperately, the Adani Group has been reported to be the front-runner for acquiring the cement assets of the Jaypee Group. It acquired Ambuja Cements and ACC from Holcim last month.

The two acquisitions herald further consolidation in the cement sector as leading companies set aggressive capacity expansion targets.

Experts have said the aggressive capacity expansion by large cement makers will impact the smaller players, leading to consolidation in the sector.

Large cement makers like UltraTech Cement and the Adani Group with its Ambuja Cements and ACC units, have better bargaining power given their scale, which helps them achieve lower cost of production compared to their smaller rivals.

They also tend to have better distribution channels, which helps them improve their market share and capacity utilisation, experts added. They believe that a rapid expansion in manufacturing capacity by large cement makers will further tip the scales in their favour.

BUSINESS LINE
DATE : 12/10/2022 P.NO.8

Broader trend remains bearish for copper

Akhil Nallamuthu
bl. research bureau

Copper futures on the MCX are moving without an intent. The October contract (expiring on October 31) has been oscillating in the range of ₹635-675 since the beginning of September. It is currently trading around ₹650.

Unless either of ₹635 or ₹675 is breached, we cannot predict the next leg of trend with confidence. Yet, the broader trend remains bearish. The contract can probably turn the short- and medium-term trend positive if it can overcome the barrier at ₹700. Resistances above ₹700 are at ₹720 and ₹760.

If the contract resumes the downtrend and breaches the nearest key support at ₹635, it will most probably fall swiftly to the subsequent support at ₹590. Below that, ₹550 is a strong support against which the contract can see a recovery.

Going forward, tighten the stop-loss to ₹670 if the contract slips below the support of ₹600 and move it further down ₹615 when the price touches ₹585.

Exit the shorts at ₹550. For fresh positions, go short if there is a rally to ₹675.

DAINIK BHASKAR DATE : 13/10/2022 P.NO.9

3 दिवसीय 'मिनकॉन-2022' कल से

- गडकरी, जोशी और फडणवीस रहेंगे उपस्थित

व्यापार प्रतिनिधि | नागपुर

विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल (वेद), एमएम एक्टिव और एमएसएमई (महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन) द्वारा चिटनवीस सेंटर में 14 से 16 अक्टूबर तक खान, खनिज और धातु से संबंधित 3 दिवसीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी 'मिनकॉन-2022' का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय खान मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में होगा। अन्य अतिथियों में राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खनन विभाग मंत्री दादाजी भूसे का समावेश रहेगा। सम्मेलन में एमएसएमसी के चेयरमैन एड. आशीष जायसवाल और एमडी एम. जे प्रदीप चंद्रेन शामिल होंगे। आयोजन को खान मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद (एमईडीसी) का सहयोग प्राप्त है।

राष्ट्रीय वक्ता करेंगे संबोधन

मिनकॉन के कन्वेनर शिवकुमार कॉर्पोरेट नेता और औद्योगिक दिग्गज प्रमुख तकनीकी सत्रों को संबोधित करेंगे, जिसमें खनन से रोजगार सृजन, मध्य भारत में वर्तमान खनिज संसाधन और इसकी मूल्य श्रृंखला, खनन क्षमता में सुधार के लिए डिजिटलीकरण और नवाचार, खनिज उद्योग के विकास में राज्य खनन निगमों की भूमिका, उद्यमियों के लिए अवसर, अन्वेषण, चुनौतियां आदि पर फोकस रहेगा। तीसरे और अंतिम दिन, विक्रेता विकास कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे करेंगे। इस खंड में एमएसएमई-महाराष्ट्र के पीएम पालेवार मुख्य वक्ता रहेंगे। डब्ल्यूसीएल और मॉयल द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

जरूरत के अनुसार आपूर्ति नहीं

एमएसएमसी के चेयरमैन एड. आशीष जायसवाल ने बताया कि देश में माइनिंग का सर्वाधिक क्षेत्र नागपुर में है और राज्य के उद्योगों को आवश्यकता के अनुसार कोयले की आपूर्ति नहीं की जाती है। वेकोलि प्रतिमाह उद्योगों को 60 हजार टन कोयला देती है, जबकि मांग 2 लाख टन की है। आवश्यकता पूरी करने के लिए उद्योगों को मजबूरन निजी कंपनियों से महंगे दर पर कोयला खरीदना पड़ता है। सम्मेलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि यहां के उद्योगों को

BUSINESS LINE DATE : 13/10/2022 P.NO.8

Imerys to expand production capacity, R&D at Vizag plant

G Naga Sridhar
Hyderabad

Mineral-based specialty solutions provider, Imerys, will expand its production capacity, research & development and sustainability efforts at its manufacturing plant in Visakhapatnam.

The ₹350-crore plant currently has a capacity to produce 30,000 tonne of calcium aluminate binder for use in the Indian refractory and construction industries.

"Imerys plans to expand capacity to 50,000 tonnes by 2030, to serve rising demand from the domestic steel and cement sectors, which continue to add capacity across the country. This makes the Vizag facility, the single largest site and investment in India for Imerys' refractory, and construction businesses," the company said in a release on Wednesday.

At the formal inauguration of the existing plant in Visakhapatnam held today in the presence of Emmanuel Lenain, the French Ambassador to India, Philippe Bourg, Senior Vice-President, Imerys said: "India is the second largest steel and cement manufacturer in the world and therefore a key market for Imerys. We have been present in India for decades through imports." In 2021, it generated sales of over ₹160 crore.

STRONG WILLINGNESS

"Imerys has a strong willingness to keep on growing and reinforce our presence in the Indian refractory market but also in the infrastructure sector with sustainable solutions," he added.

Segi Idicula, Managing Director, Imerys India added: "Our Visakhapatnam facility will address the strong demand for refractories and other high temperature materials, essential to support the growing steel, cement and other metallurgical industries."

As part of its strong focus on developing bespoke products for the local markets, Imerys is also in the process of setting up a regional Research & Development Centre at Visakhapatnam. Imerys expects that it will also contribute to augmenting the company's global technical and manufacturing standards.

While the company remains focussed on serving Indian demand, the Vizag manufacturing facility is well equipped for servicing overseas markets such as Asia Pacific and West Asia.

BUSINESS LINE
DATE :13/10/2022 P.NO.9

COMMODITY CALL.

Go long on lead at the current level of ₹181

Akhil Nallamuthu
bl.research bureau

In the past month, prices of lead futures on the Multi Commodity Exchange (MCX) have fluctuated between ₹175 and ₹182. The nearest expiry, i.e, the October series, is now trading at ₹181.

Since lead futures have been charting a sideways trend and are now hovering around the range top, ideally, one should expect the contract to see a decline from here. Especially given that ₹184 is a strong resistance where a falling trendline also coincides. However, there are reasons for some optimism.

The cumulative Open Interest (OI) of lead futures on the MCX has considerably increased to 1,259 contracts on October 11 compared with 694 contracts on August 31.

Also, the RSI and the MACD on the daily chart have recently entered the bullish region. So, the odds of breaking the barrier at ₹184 seem to be improving. Therefore, we recommend that traders consider fresh longs.

TRADE STRATEGY

Considering the recent long build-up, one can risk buying MCX lead futures at the current level of ₹181 with a stop-loss at ₹178. Move the stop-loss up to ₹182 if the contract breaks out of ₹184. Further, when the contract rallies past ₹188, tighten the stop-loss to ₹185. Exit the longs at ₹192 since the price band of ₹192-195 is a strong hurdle to cross.

LOKMAT (HELLO NAGPUR) DATE : 13/10/2022 P.NO.2

तीन दिवसीय 'मिनकॉन' आजपासून

खाण, खनिज, धातूंवर विशेष भर

नागपूर : राज्यातील खाण, खनिज आणि धातूंची उपलब्धता आणि उपयोगितेवर प्रकाश टाकणाऱ्या 'मिनकॉन-२०२२' या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन शुक्रवार, १४ ऑक्टोबरपासून चिटणवीस सेंटर, सिव्हील लाईन्स येथे होणार आहे. या अंतर्गत प्रदर्शन, परिषदा आणि व्हेंडर विकास कार्यक्रम होईल. आयोजन विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल (वेद), एमएम. ॲक्टिव्ह आणि महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळ (एमएसएमसी) यांच्यावतीने आणि राज्य सरकार व केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाच्या सहकार्याने होत आहे.

उद्घाटन १४ रोजी सकाळी १०.३० वाजता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होईल. या प्रसंगी केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे खाण व बंदरे विकास मंत्री दादा भुसे, महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आशिष जयस्वाल उपस्थित राहतील. १५ रोजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार आशिष जयस्वाल आणि १६ रोजी समारोपीय कार्यक्रमाला केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे आणि तीनही दिवस वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, राहुल उपगन्लावार, शिवकुमार राव आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित राहतील.

BUSINESS LINE
DATE :13/10/2022 P.NO.9

Demerger of NMDC Steel from NMDC okayed

Abhishek Law
New Delhi

The Ministry of Corporate Affairs has approved the demerger of NMDC Steel from NMDC Ltd. The yet-to-be commissioned 3 mtpa steel plant at Nagarnar in Chhattisgarh, has been built at an investment of ₹20,000 crore.

"The sanction of the Central government is hereby accorded to the Scheme of Arrangement of NMDC Ltd (Demerged Company) and NMDC Steel (Resulting Company). The scheme shall be binding on the shareholders and creditors of the demerged company and resulting company and all concerned with effect from April 1, 2021," the order said.

LOKMAT DATE : 14/10/2022 P.NO.8

कोळसा मंत्र्यांना पुरवठा निश्चित करण्याची होणार मागणी

उद्योगांना द्यावे लागतेय दुप्पट शुल्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : विदर्भात ११ कोटी टन खनिजाचे खनन होते. यात ६५ मिलियन टन कोळशाचा समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोळसा उपलब्ध झाल्यानंतरही विदर्भातील उद्योगांना त्यासाठी दुप्पट मूल्य चुकवावे लागत असल्याची स्थिती आहे.

वेदच्यावतीने आयोजित उत्खनन संमेलन : मिनकॉनसाठी शहरात आलेले कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विदर्भातील उद्योग क्षेत्र वेकोलिच्यावतीने कोळसा पुरवठा निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येऊ शकते. विदर्भात एकूण ११ कोटी टन खनिजाचे खनन होते. यात कोळशासोबतच ३५ मिलियन टन चुनखडी, मँगनीज आणि लोहाचे खनन होते. परंतु विदर्भाला याचा लाभ मिळत नसून बहुतांश खनिज बाहेर जात आहे. सर्वात वाईट स्थिती कोळशाची, आहे. मोठ्या प्रमाणात कोळसा असल्यानंतरही उद्योगांना त्याचा तुटवडा भासत आहे. ६ ते ७ हजार रुपये टनाचा कोळसा उद्योगांना १२ हजार टनाच्या दराने खरेदी करावा लागत आहे. काळाबाजार वाढीस लागला आहे. वेदचे उपाध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी यांच्या मते, बंद पडलेल्या खदानी पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत. यामुळे परिसराचा विकास होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

NAVBHARAT DATE : 14/10/2022 P.NO.4

NMDC का ICT और रेलटेल से करार

हैदराबाद. खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनएमडीसी और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने कॉरपोरेट कार्यालयों और खनन परिसरों दोनों में एनएमडीसी की आईसीटी और डिजिटल परिवर्तन सेवाओं को कवर करते हुए एक करार किया है. इस आशय के समझौता ज्ञापन पर एनएमडीसी के सीएमडी सुमित देब की उपस्थिति में एनएमडीसी के महाप्रबंधक (सीएंडआईटी) एच सुंदरम प्रभु और रेलटेल के कार्यकारी निदेशक मनोहर राजा ने हैदराबाद में एनएमडीसी के मुख्यालय में हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर कंपनी के निदेशक (वित्त) अमिताभ मुखर्जी, सोमनाथ नंदी, दिलीप कुमार मोहंती उपस्थित थे. सुमित देब ने कहा कि यह साझेदारी संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी जिससे खनन क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा.

NAVBHARAT DATE : 14/10/2022 P.NO.3

सम्मेलन सह प्रदर्शनी मिनकॉन का होगा शुभारंभ

खनिज संपदा पर आज से मंथन

नागपुर. विदर्भ की खनिज संपदा में चर्चा करने के लिए शहर में 3 दिवसीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी 'मिनकॉन' का आयोजन 14 से 16 के बीच किया जा रहा है. इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहेंगे और विदर्भ की विकास संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे. चिटणवीस सेंटर में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी के हाथों होगा. इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खनन मंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र माइनिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आशीष जायस्वाल उपस्थित रहेंगे. सत्र के दूसरे दिन राज्य के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटिल, उदय सावंत, तीसरे दिन 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उपस्थित रहेंगे.

महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि. ने इसका आयोजन किया है, जबकि वेद नॉलेज पार्टनर हैं. चेयरमैन आशीष जायस्वाल ने कहा कि राज्य में खनिज नीति बनाना काफी महत्वपूर्ण है. इस दौरान खनिज नीति के दस्तावेज को पेश किया जाएगा. 2019 में भी नीति बनाने की पहल की गई थी लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. इस बार हम आशावान हैं कि नीति बनेगी जिसका विदर्भ को लाभ होगा. तीन दिनों में खनिज क्षेत्र से जुड़ीं कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और वे अपने विचार रखेंगे.

रामटेक में क्लस्टर की पहल : उन्होंने बताया कि कोयला, मैंग्नीज से भरे क्षेत्र रामटेक में माइंस क्लस्टर बनाने की पहल की जा रही है. इस अवसर पर इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी.

NAVBHARAT DATE : 14/10/2022 P.NO.4

छोटे उद्योग चाहते हैं उन्हें मिले कोयला

विदर्भ का कोयला मिले विदर्भ को, कोयला मंत्री जोशी शहर में, मिलेंगे उद्यमी

उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों के लिए कटौती, सारा कोयला जा रहा पावर प्लांट

■ नागपुर, व्यापार प्रतिनिधि. देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एमएसएमई सेक्टर को पिछले काफी समय से कोयला हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. उस पर भी कोटा कम होने से मार्केट में रेट हजारों रुपये प्रति टन बढ़ गए हैं. ई-ऑक्शन नहीं होने, कोटा कम करने से मार्केट में कोयला का रेट जबरदस्त बढ़ गया है. रेट में वृद्धि होने के कारण उद्यमियों, छोटे-छोटे ईंट भट्ठों एवं सूक्ष्म इकाइयों के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं. वे किसी भी कीमत पर कोयला लेने के लिए राजी हो रहे हैं ताकि उद्योग को चलाया जा सके. इसी का लाभ सभी उठा रहे हैं.

कोयला मंत्री शहर में हैं. ऐसे में उद्योग जगत चाहता है कि वे विदर्भ के उद्योगों के साथ न्याय करें. खासकर तब जब कोयला विदर्भ का है और विदर्भ के उद्योगों को ही वह उचित दरों पर नहीं मिल रहा है या अधिक कीमत देकर लेना पड़ रहा है. इस संबंध में शुक्रवार को उद्यमियों का दल कोयला मंत्री से मिलकर गुहार भी लगाने वाला है. पावर प्लांटों का पेट पिछले कुछ दिनों में काफी बड़ा हो गया है. इन्हें जितना भी कोयला दिया जा रहा है वह कम पड़ रहा है. कोयला कंपनियों का दम पावर प्लांट को कोयला देने में ही निकल रहा है.

1,200 रुपये टन में कोयला

पावर प्लांट को कोयला कंपनियां विशेष कीमतों पर कोयला आपूर्ति करती हैं. यह बाजार रेट से काफी कम होता है. पावर प्लांट के लिए कोयले की कीमत 1,200 रुपये टन तय है, जबकि इस वक्त बाजार में कोयला 8,000-9,000 रुपये प्रति टन के भाव से बिक रहा है. कोल कंपनियां इसके बावजूद धड़ाधड़ पावर प्लांट को कोयला दे रही हैं. जानकारों का कहना है कि पावर प्लांट वाले जानबूझकर तय कोटा से कहीं अधिक कोयला ले रहे हैं. इससे सभी पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

कोयले के अलग-अलग भाव

8,500-10,500	12,500-13,200	12,000-14,000	1,200
ई-ऑक्शन का रेट	खुले बाजार में	आयातित कोयला	पावर प्लांट का कोयला

(5 फीसदी जीएसटी अलग)

मार्केट में प्रीमियम बढ़ा

1. उद्योगों को लिंकेज के तहत वेकोलि से मोटे तौर पर 3,600-3,700 रुपये टन के हिसाब से कोयला मिलता है लेकिन शार्टेज के कारण प्रीमियम बढ़कर 7,500-9,000 रु. तक पहुंचा.
2. कोयला आपूर्ति में कटौती की घोषणा से मार्केट में और आग लग चुकी है और बताया जाता है कि 1,000-1,500 रुपये प्रति टन की वृद्धि हो गई है.
3. कुछ खदानों का कोयला मार्केट में 9,400-10,500 रुपये तक पहुंचने की भी जानकारी है. यानी छोटे-छोटे उद्योगों को कोयले के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.

ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि औद्योगिक माल आने वाले दिनों में और बढ़ना तय है.

कैसा आत्मनिर्भर भारत

छोटे एवं लघु उद्योगों को मदद के लिए केंद्र सरकार भरपूर कदम उठा रही है ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके. वहीं दूसरी ओर कोयला कंपनियों से उद्योग को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है. बाजार से ऊंची-ऊंची कीमतों पर कोयला खरीदकर उद्योग चलाना मुश्किल होता जा रहा है. उम्मीद है कि सरकार उद्योगों की बात सुनेगी और उद्योग को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

- विशाल अग्रवाल, अध्यक्ष, VIA

उद्योग चलाना मुश्किल

आज सभी चाहते हैं कि उद्योग-धंधा फले-फूले लेकिन जब स्पोर्ट करने की बात आती है तो हर कोई परेशानी ही खड़ा करता है. कोयला उद्योग के लिए मूल कच्चा माल है. हजारों उद्योग इसी पर आश्रित हैं. ऐसे में कोयले का कोटा कम करना न्यायसंगत नहीं है. इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार की जरूरत है.

- नितिन लोणकर, अध्यक्ष, BMA

वहीं दूसरी ओर छोटी-छोटी इकाइयां कोयले के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर हैं. तालमेल के अभाव में यह संकट खड़ा हो गया है. वास्तव में वेकोलि का उत्पादन 17 फीसदी बढ़ा है और डिस्पैच में भी 34 फीसदी का इजाफा हुआ है. कोयला कंपनियों को कोयले की आपूर्ति 100 फीसदी से अधिक की गई है, इसके बाद भी वेकोलि ने उद्योगों का कोयला काट दिया है.

ई-ऑक्शन में कम कोयला : जानकार बताते हैं कि विदर्भ के उद्योगों के लिए 5-6 लाख टन तक कोयले की जरूरत है. उद्योगों को ई-ऑक्शन से कोयला लेने को कहा जाता है लेकिन ई-ऑक्शन में महज 2-2.5 लाख टन कोयले का ही ऑक्शन किया जाता है. यह भी भेद खुल चुका है कि कई डमी कंपनियां जानबूझकर कोयले की बोली ऊंची कीमतों पर लगाती हैं और बाद में कोयला नहीं खरीदतीं. इससे मार्केट में कोयला का रेट बढ़ जाता है और खामियाजा उद्योगों को उठाना पड़ता है. इसलिए उद्यमी ई-ऑक्शन के जरिए कम से कम 5-6 लाख टन कोयला देने की मांग कर रहे हैं.

DAINIK BHASKAR DATE : 14/10/2022 P.NO.14

वीआईए ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा पत्र

विदर्भ में उद्योगों को मांग के अनुसार नहीं हो रही है कोयले की आपूर्ति

नागपुर। विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (वीआईए) ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर विदर्भ के उद्योगों को उनकी मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। कोयला मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि क्षेत्र के उद्योगों को अपना प्लांट संचालित करने के लिए प्रमुख कच्चा ईंधन कोयला है, जो उन्हें वेकोलि से एफएसए (एलए) / ई-नीलामी मोड के माध्यम से खरीदना पड़ता है। बावजूद इसके उद्योगों को मांग के अनुसार कोयला नहीं मिलता है। क्षेत्र में अधिकांश इकाइयों को अपने बॉयलर चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है।

उद्योगों का हो रहा भारी नुकसान

राज्य जेंको और ईपीपी को पिछले एक वर्ष से डब्ल्यूसीएल की सभी खदानों से नियमित आधार पर प्रथमिकता से कोयला आपूर्ति की जा रही है, जबकि सीआईएल के दिशा-निर्देशों के अनुसार डब्ल्यूसीएल ने पिछले एक साल से एफएसए (एलए) आवंटित उद्योगों और एमएसएमई के लिए कोयला आपूर्ति में 25 प्रतिशत की कटौती की है। कम आपूर्ति के कारण उद्योग अपने संयंत्र 100% क्षमता पर नहीं चला पा रहे हैं, जिससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता काफी कम हो गई है और भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर वेकोलि, नागपुर का उत्पादन बढ़ा है। बावजूद इसके क्षेत्र के उद्योगों को कोयले की कमी और अपर्याप्त कोयला स्टॉक का बहाना बताकर नियमित आधार पर कोयले की वैध मात्रा और आवश्यक ग्रेड नहीं मिल रहे हैं। अधिकांश एमएसएमई व अन्य उद्योग अपने उद्योगों को नियमित चलाने के लिए लिंकेज नीलामी एफएसए/ ई-नीलामी मोड के माध्यम से कोयला खरीद रहे हैं।

BUSINESS LINE
DATE:14/10/2022 P.NO.10

Aluminium: Stay away from fresh bets

Akhil Nallamuthu
bl. research bureau

Prices of aluminium started recovering towards the end of last month. The metal's October contract on the Multi Commodity Exchange (MCX) took support at ₹188 and has now increased to ₹210.

As the price rallied, there have been long build-ups revealing the arrival of fresh buyers. But this week, there is a dip in the cumulative Open Interest (OI), hinting buyers prefer profit booking.

The likelihood of traders booking profits is higher given that the contract is approaching the resistance band of ₹218-220.

Therefore, fresh longs are not suggested and going short, too, is not a good idea, given some more room is left to rally.

TRADING STRATEGY

One can consider longs when the contract decisively breaches ₹220 or initiate short positions if the aluminium futures exhibit signs of bearish reversal after reaching ₹220. Until then, traders can stay away from executing new orders.

In case of holding buys, book profits at ₹218 and can re-enter if the resistance band of ₹218-220 is breached.

On the other hand, traders with short positions can hold with a stop-loss at ₹222 since there are chances of reversing lower from the ₹218-220 region.

THE HITAVADA (CITYLINE) DATE : 15/10/2022 P.NO.1

India will stop import of thermal coal by 2024-25: Coal Minister

■ Business Bureau

HIGHLIGHTING the attempt of the Central Government to minimise the country's dependency on others, Union Minister for Coal and Mines Pralhad Joshi on Friday said that India would stop import of thermal coal by 2024-25. He said that the domestic production of coal in the country would see new highs in the current year as the reforms in the sector were yielding good results. He was speaking at the

(Contd on page 2)

Union Minister for Coal and Mines Pralhad Joshi lighting the traditional lamp to mark inauguration of 'MINCON-2022' on Friday. Union Minister Nitin Gadkari, State Forest Minister Sudhir Mungantiwar; State Minister for Mines Dadaji Bhuse, Chairman, MSMC Adv Ashish Jaiswal, MP Krupal Tumane, Principal Secretary (Industries) Harshadeep Kamble and others also are seen.

CONTD.. ON PAGE 26

THE HITAVADA DATE : 15/10/2022 P.NO.2

CONTD.. FROM PAGE 25

India will stop import of thermal...

inaugural session of the three-conference-cum-exhibition related to mines, minerals and metals -'MINCON-2022' being held here.

The Vidarbha Economic Development Council (VED), MM Activ and Maharashtra State Mining Corporation (MSMC) are jointly conducting the event.

Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari; Maharashtra Forest Minister Sudhir Mungantiwar; Maharashtra Minister for Mines Dadaji Bhuse; Chairman, MSMC Adv Ashish Jaiswal; MP Krupal Tumane; Principal Secretary - Industries Harshadeep Kamble; former Rajya Sabha Member Dr Vikas Mahatme; President of VED Devendra Parekh; former President of VED Shiv Kumar Rao; and Ravi Boratkar of MM Activ were seated on dais.

Joshi further said that with operationalisation of various mines under the commercial coal mining auction process, the private sector will have a significant share in domestic coal production and the country's dependency on imported coal will reduce.

Expressing his willingness to accelerate the process of setting up new mines in the State, Joshi invited proposals from the Maharashtra Forest Minister and Minister for Mines and assured all possible support. "We have already given most of the powers to State Governments so that new mines could be opened as soon as possible," he said.

Joshi also said that the country's coal output in the current financial year is expected to be 900 million tonne which will further go up in coming years as the Government has allotted 47 new commercial coal blocks and auctioned 163 mines.

In his address, Gadkari said, there is a need to identify challenges in the mining sector and resolve them in a time bound manner. "When investors put their money in any project, they wish to make it operational in a scheduled time frame. But unfortunately, we see delays in various projects especially in the coal mining sector. This discourages the investors and affects coal production," he said, highlighting the need for a corruption-free, transparent and time bound mechanism to attract investors in the sector. He also spoke on a balance between environmental clearances and allocation of new mines.

On the viability of coal mines, Gadkari felt that there should be mine specific relaxation in royalty as coal explorations vary from mine to mine.

Earlier, Mungantiwar said, the 'coal and mineral producing' region of Vidarbha deserves more industries and infrastructure. "Various minerals produced are being transported to other regions for value addition. It is happening despite the fact that value addition can be done in the region. We want the Union Government to attract investors in this area," he said.

Ashish Jaiswal said, minerals are the strength of Vidarbha but people here are not getting its due benefits. "Apart from this, there is unrest among the coal consumers who are paying heavy price for the commodity," he added.

Dadaji Bhuse the State government will soon come out with a new mining policy through which the Government will boost projects for value addition of minerals in the proximity of the mining areas.

Harshdeep Kamble said, the Government is committed to attract investors in Vidarbha as it has huge mineral reserves. "It will also generate employment opportunities in the region," he said. Ravi Boratkar gave the introductory remarks while Devendra Parekh welcomed the guests. Shiv Kumar Rao gave a brief idea of the conference while Secretary-VED Varun Vijaywargi proposed the formal vote of thanks.

BUSINESS LINE DATE : 15/10/2022 P.NO.1

Centre moves to revive Kolar mines, to extract gold, rare metals

WEALTH UNDERGROUND. Seen fetching ₹30,000 cr; team studies mining solution, monetising 12,000-acre land

Dalip Singh
New Delhi

The Centre has decided to revive gold mining, auction tailing dumps and two blocks at the Kolar fields in Karnataka more than 22 years after it was shelved because the extraction of metals and minerals had become unviable.

According to an estimate by the Nonferrous Materials Technology Development Centre — the R&D arm of the Ministry of Mines — the extracts from Kolar gold fields (gold and minerals like palladium and rhodium) are likely to fetch ₹30,000 crore. The mines located in Karnataka's Kolar district are owned by Bharat Gold Mines Limited (BGML).

STILL GLITTERING. Reports by the Indian Bureau of Mines and MECL indicate that tailing dumps alone have gold worth ₹6,237 crore, sources said

HUGE RESERVES

Explorations by Mineral Exploration and Consultancy Limited (formerly Mineral Exploration Corporation Limited) in 2018 revealed that block McTaggart possesses 1.044 million tonnes (mt) of gold resources with a grade of 2.97 g/tonne. Similarly, 1.008 mt of gold resources with grade of 0.5 g/tonne lie in the other oriental block, a senior Mines Ministry official said.

BGML has 33 mt of gold tailing. The Ministry has got two studies done to ascertain resources in the tailing dumps. Reports by the Indian Bureau of Mines (IBM) and MECL indicate that tailing dumps have gold worth ₹6,237 crore, sources said. The Ministry is now exploring the possibility of mineralising the resources there and monetising over 12,000 acres freehold land of BGML.

UNUSED RESOURCES

"The rich resource at Kolar gold mines has remained unutilised for long and the effort now is to give it back to the people," Farida Mahmood Naik, Joint Secretary in the Mines Ministry, told *businessline*, confirming the government's initiative.

Mines Secretary Vivek Bhardwaj had led a delegation of officials from the Centre and State governments to the Kolar mines on Wednesday to figure out an early solution for gold mining and monetisation of the land along the Bengaluru-Chennai highway.

Alternatively, a rail network to connect the two metros will also give a fillip to the Centre's plan of having an industrial hub on the land which has been lying unused, said sources.

DETAILED STUDY

Earlier, the Ministry had constituted a monitoring committee comprising chiefs of MECL and BGML and officials from the Geological Survey of India, IBM and the Ministry itself for a legal review, asset valuation and hiring of a technical consultant for a techno-economic feasibility report and a management consultant to suggest the way forward.

The committee had also gone into past hurdles such as inability to execute a 2006 Cabinet decision to sell BGML's assets due to litigation. The erstwhile Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) had ordered the winding up of BGML in 2000.

The latest move is part of a larger exercise wherein six gold mines have already been auctioned by the States in the last five years.

DAINIK BHASKAR (NAGPUR BHASKAR) DATE : 15/10/2022 P.NO.16

2024-25 तक थर्मल कोयले का आयात बंद करेंगे : प्रहलाद जोशी

खनन क्षेत्र पर आधारित उद्योग ही विदर्भ को आगे ले जा सकते हैं : गडकरी

नागपुर में खनिज, धातु पर आधारित परिषद 'मिनकॉन -2022' उद्घाटित

व्यापार प्रतिनिधि | नागपुर

कृषि और उद्योग के बाद खनिज और खनन क्षेत्र ही रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। सन 2047 तक भारत को विकसित देश के रूप में पहचान दिलाने में दो क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह विचार केंद्रीय संसदीय कामकाज व कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने व्यक्त किए। महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडल, विदर्भ आर्थिक विकास परिषद द्वारा संयुक्त रूप से 'मिनकॉन 2022' के दूसरे संस्करण का आयोजन नागपुर के चिटणवीस सेंटर में किया गया है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जोशी बोल रहे थे। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने की। सांसद कृपाल तुमाने, राज्यसभा सदस्य विकास महात्मे, वन और पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खनिज मंत्री दादाजी भुसे, महाराष्ट्र वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव हर्षदीप कांबले, महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडल के अध्यक्ष आशीष जैस्वाल, विदर्भ आर्थिक विकास परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र पारिख, कार्यक्रम के संयोजक शिवकुमार राव, एमएम एक्टिव के एमडी रवि बोरटकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

जोशी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 900 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 163 खदानों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का संघराज्य पद्धति पर विश्वास है, इसीलिए प्रधानमंत्री राज्यों को इस क्षेत्र के लिए अधिकांश अधिकार देने के पक्ष में है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में विदर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

कोयला मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश की खनिज संपत्ति का मूल्य 1.9 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार इस संपत्ति का योग्य उपयोग और वितरण करने के लिए कटिबद्ध है। देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में विदर्भ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। नई कल्पना, नए संशोधन को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है।

खनन क्षेत्र और जंगल पर ही विदर्भ के विकास की नींव : गडकरी

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने कहा कि, खनन क्षेत्र और जंगल पर ही विदर्भ के विकास की नींव है। इसीलिए इन क्षेत्रों से जुड़े उद्योगों से ही विदर्भ का विकास हो पाएगा। राज्य का 75% खनिज और 80% वनसंपदा विदर्भ में उपलब्ध है। इस संपदा का उचित तरीके से उपयोग करने पर ऊर्जा क्षेत्र में विदर्भ की भागीदारी बढ़ेगी। गडकरी ने कहा कि बिजली नहीं तो उद्योग नहीं, उद्योग नहीं तो विकास नहीं होगा, इसीलिए हमें अब ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की जरूरत है। देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल, ऊर्जा, परिवहन, संवाद क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए परिवर्तन के कारण कोयला उत्पादन बढ़ा है। देश में बिजली उत्पादन बढ़ा है और बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। मांग को पूरा करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी,और यह आवश्यकता विदर्भ ही पूरी कर सकता है। गडकरी ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी आधुनिक कार्यप्रणाली का उपयोग कर समय की बचत करें। राज्य सरकार समय पर और पारदर्शी तरीके से लाइसेंस उपलब्ध कराए। कोयले से अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया का निर्माण कर देश में 60 हजार करोड़ रुपए का यूरिया आयात कम किया जा सकता है। 17 लाख करोड़ का ईंधन आयात कम करने के लिए इस क्षेत्र को नई नीति बनानी होगी। बंद खदानों को शुरू करने के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है।

विदर्भ में खनिज संपदा पर आधारित उद्योग लगे : मुनगंटीवार

वन आणि पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि विदर्भ पर्यावरण की दृष्टि से संपन्न है। विदर्भ की खनिज संपत्ति पर आधारित उद्योग यहीं पर लगने चाहिए। चालू आर्थिक वर्ष में राज्य को खनिज संपत्ति से 2475 करोड़ की आय होगी। इसमें अकेले 1082 करोड़ रुपए का योगदान चंद्रपुर शहर का रहेगा।

खनन मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के कारण यदि लौह उत्पादन के लिए सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की ओर से गति प्रदान की जाती है, तो महाराष्ट्र के साथ ही विदर्भ को भी लाभ होगा और राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। खनन के कारण रुके हुए क्षेत्रों को विकास निधि की आपूर्ति की जिम्मेदारी हमारे विभाग की है और हमारी ओर से इस पर काम किया जा रहा है। राज्य में जल्द ही नई खनिज नीति लागू होगी। इसमें सभी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सहयोग करना होगा।

अधिकारियों पर बरसे गडकरी, पत्नी से ज्यादा फाइल से प्यार

अपने भाषण के दौरान फिर एक बार गडकरी ने अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए कितना समय लगता है यह राज्य सरकार का मामला है। राज्य में अनेक कोयला खदानों की नीलामी हुई है, लेकिन भूमि अधिग्रहण न होने के कारण खदानें शुरू नहीं हो पाईं। जमीन अधिग्रहण के लिए भी ब्लैकमेलिंग की जाती है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूसीएल के अधिकारी नकारात्मक सोच और केंद्र सरकार के अधिकारी होने के घमंड में काम करते हैं। उन्हें कोयला उत्पादन बढ़ाना चाहिए। राज्य हमारा है। हम जैसा बोलेंगे, वैसे सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा-अधिकारी पत्नी से ज्यादा फाइल से प्यार करते हैं, इसीलिए वे फाइल दबाकर रखते हैं।

NAVBHARAT (NAGPUR PLUS) DATE : 15/10/2022 P.NO.1

वन, खनिज से विदर्भ का विकास

■ नागपुर, व्यापार प्रतिनिधि. विदर्भ का विकास वन और खनिज संपदा पर निर्भर है. इससे संबंधित उद्योग लगाकर ही विदर्भ आत्मनिर्भर बन सकता है लेकिन इन दोनों सेक्टरों में बाधाएं भी काफी हैं. इनका हल नेताओं को निकालना होगा. केंद्र और राज्य सरकार को तत्काल बाधाओं को पाइंटआउट करना होगा और समाधान निकालना होगा, अन्यथा कोई भी अधिकारी इसके लिए इच्छुक नहीं रहता. वे अपना काम चलाते रहते हैं. इससे क्षेत्र पिछड़ जाता है और जनता नेताओं को कोसती है. इन परिस्थितियों से पार पाने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और टाइमबाउंड कार्य योजना तैयार करनी होगी. यह विचार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिनकॉन कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर रखे. चिटणवीस सेंटर में महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन (एमएसएमसी) और वेद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य एवं कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी, खनन मंत्री दादा भुसे, मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधान सचिव हर्षदीप कांबले, एमएसएमसी चेयरमैन आशीष जायस्वाल, कृपाल तुमाने उपस्थित थे.

काफी आक्रामक मूड में गडकरी : गडकरी काफी आक्रामक मूड में थे और मंत्री और केंद्रीय कंपनियों को टाइमबाउंड काम निपटाने की नसीहत दे रहे थे. उनका स्पष्ट कहना था कि जो समय पर काम नहीं कर रहा है, वैसे लोगों को बाहर करो और देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वालों को बढ़ावा दो. आज उदासीन अधिकारियों के कारण ही विदर्भ सहित देश विकसित नहीं हो पा रहा है. कई परियोजनाएं अब तक लंबित हैं. वाजपेयी के दौर के भी प्रोजेक्ट अब तक पूरे नहीं हो पाएं हैं, जबकि इनके पूरा होने से कई सेक्टरों में आयात कम किया जा सकता था.

कई फाइलें अटकी हैं... : उन्होंने मुनगंटीवार से कहा कि आप देखो, आज आपके विभाग में ही कई फाइलें अटकी हैं. माइनिंग, सड़क से जुड़ीं फाइलों को बाबू लटका रहे हैं. इसकी जानकारी मंत्री को होनी चाहिए. बैठक कर इसका निदान निकालना चाहिए. उन्होंने 'सैंड माफियाओं' का भी जिक्र किया और जोशी से कहा कि अगर कोयला के साथ कोल इंडिया सैंड निकालता है तो गरीबों को कम कीमत पर घर मिल सकता है. उन्होंने कहा कि विदर्भ की बड़ी-बड़ी कंपनियां लाभ कमा रही हैं लेकिन लाभ को निवेश अटकी हैं. आयोजकों से भी प्रश्न किया और उन्हें विस्तृत एजेंडा तैयार करने को कहा ताकि आयोजन का लाभ मिल सके.

निवेशकों को न रोकें : गडकरी ने स्पष्ट किया कि जो लोग निवेश करने के इच्छुक हैं, वैसे लोगों को रोकना गलत है. फाइलें जल्दी क्लियर होनी चाहिए ताकि वे समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट पूरा कर सकें. ब्याज का मीटर चलने लगता है और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है. यह देश के हित में नहीं है.

वोकल फॉर लोकल बनो : जोशी कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि खनिज क्षेत्र में भी वोकल फॉर लोकल बनना चाहिए. प्रधानमंत्री का यही सपना है कि देश इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बने. यही कारण है कि पीएम के मार्गदर्शन में 2021 में माइनिंग से संबंधित 90 फीसदी अधिकार राज्यों को दे दिए गए हैं. 10 फीसदी ही केंद्र के पास हैं. जो राज्य गंभीर होकर काम कर रहा है वह कई गुना बढ़ रहा है. महाराष्ट्र भी वोकल फॉर लोकल बन सकता है और राजस्व में इजाफा हो सकता है. निवेश के द्वार खुल सकते हैं. मैं इतना कह सकता हूं कि सारे प्रस्ताव के साथ दिल्ली आएं और उनका समाधान निकालें ताकि विदर्भ में अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके.

मिनकॉन का उद्घाटन कर गडकरी ने रखे विचार

लाएंगे नई नीति

भुसे ने कहा कि विदर्भ में प्रचुर खनिज है. इसकी प्रक्रिया भी स्थानीय स्तर पर हो, राज्य सरकार का यही प्रयास रहेगा. राज्य सरकार जल्द से जल्द खनिज नीति पेश करेगी ताकि राज्य में निवेश आकर्षित किया जा सके. हम जल्द केंद्र सरकार के सहयोग से अधिक से अधिक खदानों को चालू करने पर काम करेंगे.

विदर्भ को मिले न्याय

मुनगंटीवार ने कहा कि विदर्भ को न्याय मिलना चाहिए. सर्वाधिक नुकसान हम उठा रहे हैं लेकिन लाभ कोई और ले रहा है. प्रधान सचिव कांबले, शिवकुमार राव, देवेंद्र पारख मंच पर उपस्थित थे. वेकोलि के सीएमडी मनोज कुमार, मॉयल के सीएमडी मुकुंद चौधरी भी उपस्थित थे.

थर्मल कोयला आयात होगा बंद

जोशी ने बताया कि 2024-25 तक देश में थर्मल कोल का आयात को बंद कर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री का यह स्पष्ट निर्देश है. यही कारण है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरलीकरण किए जा रहे हैं. इसका असर भी दिखने लगा है. 2014 में देश में 572 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ, 2020 में यह 700-800 मिलियन टन रहा, जबकि 2023 में 900 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि घरेलू उत्पादन इतना होगा.

आज आएंगे देवेंद्र, सावंत

मिनकॉन के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्योग मंत्री उदय सावंत सुबह 10 बजे कार्यक्रम में संबोधित करेंगे.

फिर झलका दर्द

■ गडकरी का दर्द पुनः झलका. उन्होंने भाषण के दौरान पुनः कहा, '1 लाख करोड़ का मुंबई-दिल्ली प्रोजेक्ट 2 वर्ष में कर लिया लेकिन मेरे घर के सामने वाली 1 किलोमीटर की सड़क 11 वर्षों में नहीं बनवा पाया. कई अधिकारी आते हैं तो चेहरा देखकर शर्म आती है लेकिन मैं भी मजबूर हो गया हूं.'

■ मुनगंटीवार ने कहा, 'चंद्रपुर में किसी अमेरिकन को एक रात सुला दो, दूसरे दिन वह अफ्रीकन बन जाएगा. चंद्रपुर में इतना प्रदूषण हो चुका है लेकिन कोई भी एजेंसी इस पर काम नहीं कर रही है.'

++